

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 19/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जयें :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री गोविन्द लाल उम्र 65 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द यादव जाति यादव निवासी हॉस्पिटल रोड बारों (मालिक एवं विक्रेता) मेसर्स पारस किराना स्टोर, हॉस्पिटल रोड बारों जिला बारों।
2. श्री महेश कुमार पुत्र श्री गोविन्द लाल जाति यादव निवासी हॉस्पिटल रोड बारों (खाद्य रजिस्ट्रेशन धारी) मेसर्स पारस किराना स्टोर, हॉस्पिटल रोड बारों जिला बारों।
3. श्री सतीश डॅंग उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री गुलशल निवासी हॉस्पिटल रोड बारों। मेसर्स भोलेनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, हॉस्पिटल रोड बारों।
4. सुनीता उम्र 32 वर्ष पत्नि श्री राहुल जामड निवासी 31-के, महावीर कॉलोनी, बांदनवाडा, तहसील भिनय जिला अजमेर। मेसर्स ऑसवाल मार्केटिंग, ए-1/620ए नारायण इण्डस्ट्रिज एरिया रोड न06 वी.के.आई, एरिया जयपुर।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (1) एफएसएस एक्ट 2006 विनियम 2011

- उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वयं)
2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी कम 1 व 2)
3- श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अप्रार्थी कम 3)
4- श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (अप्रार्थी कम 4)

निर्णय दिनांक 27.11.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.11.2017 को मेसर्स पारस किराना स्टोर, हॉस्पिटल रोड बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री गोविन्द लाल पुत्र श्री प्रेमचन्द यादव (मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 29.11.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस)** 1 किलो की पैकिंग में विक्रय हेतु रखे हुये थे, जिसमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से विक्रेता से **आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस)** 1 किलो ग्राम मात्रा के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 40/- रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वयं हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे **आयोडाईज्ड (फॉचून प्लस)** 1 किलो ग्राम मात्रा के 4 पैकेट को चार नमूना भाग में अलग-अलग कर, प्लास्टिक के साफ सुखे स्वच्छ डिब्बो में मूल ही भरकर प्रत्येक डिब्बो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच-787 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वयं द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 950/FSSA/Kota/ Act/2017/983 दिनांक 8.12.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड (फॉचून प्लस)** 1 किलो ग्राम पैकेट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 51 के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.7.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्जे सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 स्वयं उपस्थित रहे है एव क्रम 3 व 4 द्वारा जर्जे अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जर्जे प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने बहस परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस)** 1 किलो पैकेट का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच में **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों ने आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस) की जांच हेतु लिया गया नमूना दिनांक 29.11.2017 की जांच खाद्य विश्लेषक कोटा द्वारा की गई है जिसके आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो मिथ्या आधारों पर आधारित होने से निरस्तनीय है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमक का लिया गया नमूना एवं लिये गये नमूने की पैकिंग व उसके रख रखाव की खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियमों एवं प्रक्रिया तथा उसके प्रावधानानुसार न होने से परिवाद निरस्तनीय है। यह कि नमूने का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशाला फूड सेपटी एण्ड स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा नेशनल एक्केडिटेशन बोर्ड से टेस्टिंग एवं केलिब्रेशन का विश्लेषण करने बाबत मान्यता प्राप्त नहीं है। यह कि फूड सेपटी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा की जांच दिनांक 8.12.2017 में उक्त पदार्थ को सब स्टेण्डर्ड माना है जबकि उक्त जांच लेबोरेट्री इस प्रकार के नमूनों की जांच के लिये किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं है तथा यह दस्तावेज किसी भी रूप में ग्राहक में दस्तावेज साक्ष्य नहीं है फिर भी अप्रार्थी के विरुद्ध एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (11) का उल्लंघन मानकर परिवाद पेश किया है जो अधिनियम के विधि प्रावधानों के असंगत होने से कार्यवाही बन्द किये जाने योग्य है। परिवादी ने तथाकथित नमूना अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर माननीय विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर लिये गये हैं नमूना लेते समय नमी का ध्यान न रखने से उक्त जांच में मामूली अन्तर आया है, नमूने के लिये अपनाई गई दूषित प्रक्रिया का परिणाम है इसलिये परिवाद पूरी तरह से गलत है एवं स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा की गई खाद्य पदार्थ की सप्लाई किसी भी प्रकार से मानव जीवन के लिये घातक नहीं है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 950/FSSA/Kota/Act/2017/983 दिनांक 8.12.2017 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जयें पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पास से वास्ते नमूना जांच कर लिया गया, खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस) 1 किलो ग्राम पैकेट जांच में अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 प्रत्येक अप्रार्थी को 2500/- 2500/- रुपये पत्रावली में कुल जुर्माना राशि 10,000/- रुपये (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि पृथक-पृथक अथवा एक ही प्रतिनिधी के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जयें चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों

